

भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1307
दिनांक 25 नवम्बर, 2019

तेल और गैस के निवेश में वृद्धि

1307. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

श्री शंकर लालवानी:

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या सरकार तेल और गैस की बढ़ती मांग को देखते हुए निवेश में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व में वद्युत क्षेत्र में भारत का कौन-सा स्थान है; और

(ग) देश विशेषकर गुजरात में शहरी गैस नेटवर्क में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

क) सरकार ने फरवरी, 2019 में मौजूदा क्षेत्रों से तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को गति देने, घरेलू और वदेशी निवेश को आकृष्ट करने, अन्वेषण क्रयाकलापों को बढ़ाने के उद्देश्य से अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति में प्रमुख सुधारों को अनुमोदित किया है। इन नीतिगत सुधारों का लक्ष्य अन्य बातों के साथ साथ कार्य कार्यक्रम को अपेक्षाकृत अधिक महत्ता देते हुए अन्वेषण क्रयाकलापों को बढ़ावा देना, राजकोषीय और संवदागत शर्तों को आसान बनाना, सरकार को कोई उत्पादन अथवा राजस्व हिस्सेदारी के बिना श्रेणी II और III तलछटीय बेसनों के तहत अन्वेषण ब्लॉकों की बोली लगाना, राजकोषीय प्रोत्साहन देते हुए खोजों का शीघ्र मौद्रीकरण, वपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता के साथ गैस उत्पादन प्रोत्साहित करना, नवीनतम प्रौद्योगिकी और पूंजी का समावेशन, सहयोग के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों को कार्य करने की अधिक आजादी देना तथा नामांकन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के तरीकों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी, इलैक्ट्रॉनिक एकल वंडो व्यवस्था के साथ सहजता से कारोबार को बढ़ावा देना तथा मंजूर प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना।

ख) विश्व बैंक की रिपोर्ट में, जैसा कि वद्युत मंत्रालय ने बताया है कि: इंडिंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में "बिजली प्राप्ति" हेतु डीबीआर 2019 में भारत की रैंकिंग में सुधार होकर 24 से 22 हो गया है।

ग) 10वें सीजीडी बोली दौर के पूरा होने के साथ ही, सीजीडी 27 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में फैले 407 जिलों में 229 भौगोलिक क्षेत्र उपलब्ध होंगे, जो भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी और इसका 53 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को कवर करेगी। गुजरात राज्य के सभी जिलों को सीजीडी नेटवर्क में शामिल किया गया है।
